an>

Title: The Minister of Parliament Affairs made a statement regarding Government Business during the week commencing the 24th July 2017 and submission made by Members.

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): महोदया, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 24 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगाः–

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार [जिसमें

(i) नःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017;

(ii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017; और

(iii) कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार और पारित करना शामिल हैं] ।

2. बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का संख्या 1) का निरनुमोदन वाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार और पारित करना – अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए। (पुरःस्थापना के पश्चात)

3. पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन अध्यादेश, 2016 (2017 का संख्या 2) का निरनुमोदन वाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन विधेयक, 2017 पर विचार और पारित करना – अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए। (पुरःस्थापना के पश्चात)

4. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करनाः–

(क) केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) संशोधन विधेयक, 2017 –अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए। (पुरःस्थापना के पश्चात)

(ख) एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) संशोधन विधेयक, 2017 –अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए। (पुरःस्थापना के पश्चात)

(ग) भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2017

(घ) स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2017

(ड.) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विधेयक, 2017

(च) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017

(छ) निरसन और संशोधन विधेयक, 2017

5. वर्ष 2017–18 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (रेल सहित) से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार और पारित करना।

6. वर्ष 2014–15 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार और पारित करना।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में मेरे दो विषयों को सम्मिलित किया जाए।

1. रोहतास जिला (बिहार) के डालमिया नगर उद्योग परिसर में रेल मंत्रालय द्वारा आवधिक वैगन मरम्मत कारखाना स्थापित करने का कार्य वर्कशाप प्रोजेक्ट ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यू.पी.ओ.) पटना को सौंपा गया है। परन्तु आर्गनाइजेशन (डब्ल्यू.पी.ओ.) की शिथिलता के कारण अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है। इसे शीघ्र कार्यान्वित कराया जाए।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम (बिहार) में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतास जिला के रोहतास किला एवं कैमूर जिला के मूण्डेश्वरी धाम पर रोपवे का निर्माण शीघ्र कराया जाए।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाए : -

1. मध्य प्रदेश के मेरे संसदीय क्षेत्र के छतरपुर जिले में एन.टी.पी.सी. के शिलान्यास का कार्य 2014 के लोक सभा चुनाव के पूर्व किया गया था, किन्तु निर्माण कार्य में प्रगति काफी धीमी है। अतः पर्यावरण संबंधी स्वीकृति एवं अन्य बाधाओं को दूर कर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया जाए।

2. मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का टीकमगढ़-छतरपुर क्षेत्र चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। मेडिकल कॉलेजों के दूर होने से बड़ी संख्या में मरीजों को जान से हाथ धोना पड़ता है। अतः टीकमगढ़-छतरपुर में केन्द्र सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज खोलने की शीघ्र कार्यवाही की जाए।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदया, अगले हफ्ते की कार्य सूची में निम्नलिखित विÂषयों को जोड़ा जाए।

देश का किसान उसके उपज का भाव न मिलने की वजह से कर्ज में डूबा हुआ है। देश के सभी किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी करने की दिशा में सदन में चर्चा की मांग।

देश भर में किसानों की बढ़ती आत्महत्या तथा किसानों को फसल के दाम ठीक न मिलने के प्रति जनक्षोभ और इस परिप्रेक्ष्य में हो रही कर्ज माफी की बढ़ती मांग, देश भर में आंदोलन के माध्यम से रास्ते पर उतरा हुआ किसान, इन कारणों की वजह से बिगड़ते हुए हालातों को संभालने हेतु एवं किसानों की खुशहाली के लिए भारत सरकार द्वारा गठित स्वामीनाथन आयोग तथा भारत सरकार द्वारा इसका स्वीकारी गयी रिपोर्ट को तुरंत लागू करने के संदर्भ में चर्चा की मांग।

.....

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : महोदया, कृपया निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य सूची में शामिल करने का कष्Âट करें।

1. गुड़, राब व खाण्डसारी की मात्र 100-120 इकाइयां पूरे देश में हैं, जो लघु व सीमान्त किसान हैं, जिनके पास गन्ने के सट्टों के अलावा परिवहन के अल्प साधन हैं, जो गन्ना फैक्ट्री तक

नहीं जा पाता, उस गन्ने की आपूर्ति इन ईकाइयों में होती है, जिससे साधन विहीन किसानों को उक्त गन्ना सप्लाई द्वारा नगद भुगतान उनकी छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है तथा इन ईकाइयों से 15000 से 20000 परिवारों को रोजगार भी मिलता है।

इस लघु व कुटीर उद्योग के अस्तित्व को बचाये रखने हेतु पूर्व में इसे वैट से मुक्त रखा गया था, परन्तु अब जी.एस.टी. में इस उद्योग पर 5 प्रतिशत कर तय किया गया है। उल्लेखनीय है कि देश में बची राब, गुड़, खाण्डसारी की कुल 100-120 ईकाइयाँ बची हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में हैं तथा इनमें से मात्र 35 ईकायाँ ही खाण्डसारी का उत्पादन करती हैं, जिसमें से 22 केवल मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी में ही हैं। उक्त 35 ईकाइयों का कुल वार्Âिषक टर्न ओवर 500 करोड़ है, जिस पर 25 करोड़ टैक्स बनेगा। इस उद्योग के अस्तित्व को बचाये रखने हेतु इस उद्योग को 5 प्रतिशत जी.एस.टी. के बजाय कर मुक्त श्रेणी में रखने से सामान्य रूप से खाद्यान्नों से कर मुक्त रखने की नीति के साथ ही इस लघु उद्योग को बचाने में मदद मिलेगी।

2. राम चरित मानस की हस्तलिखित पांडुलिपि उपलब्ध होने, गोस्वामी तुलसीदास की कर्म स्थली व पांडवों के अज्ञातवास के प्रमाण सहित बहुत से ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व के मंदिर व इमारतें होने के साथ ही गोला गोकरन नाथ शिव मंदिर व दुधवा टाईगर रिजर्व फॉरेस्ट आदि अनेक धार्मिक ऐतिहासिक व पर्यटन स्थल हैं। अतः लखीमपुर को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रामायण सर्किट से जोड़ा जाये।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Madam, the urgent need to address the rise in Vector Borne diseases in the State of Kerala.

The urgent need to ensure flood prevention measures and calamity redundancy measures are in place in the State of Kerala.

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में मेरे दो विषयों को सम्मिलित किया जाए।

(एक) देश के सभी किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी पर सदन में अगले सप्ताह चर्चा।

(दो) स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर अगले सप्ताह चर्चा।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल (दमोह) : महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में मेरे दो विषयों को सम्मिलित किया जाए।

(एक) प्रधानमंत्री आवास योजना में न्यूनतम आयु 40 वर्ष है, ऐसी स्थिति में दिव्यांगों एवं निरक्षितों के लिए यह अवरोध बन रही है। इस पर मतदान की आयु के साथ शोधन पर विचार।

(दो) केन्द्रीय सेवाओं एवं प्रतिस्पर्धाओं में जाति प्रमाण का एक समान प्रारूप हो ताकि छात्रों एवं अभिभावकों का धन एवं समय बच सके, एकरूपता से भ्रष्टाचार एवं परेशानी कम होगी।

HON. SPEAKER: Smt. Pratima Mondal – not present.

Shri Mullappaly Ramachandran – not present.

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में मेरे विषय को सम्मिलित किया जाए।

(एक) आज देश को स्वतंत्र हुए 70 वर्ष पूरे होने को हैं। भारत में मुगलों का साम्राज्य रहा जो भारत पर आक्रमण कर देश को गुलाम बनाया। उसके बाद अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, लेकिन आज विडम्बना यह है कि भारत की राजधानी दिल्ली में कई मार्गों का नाम भारत पर आक्रमणकारियों के नाम पर है। जैसे बाबर रोड, अकबर, हुमायूं, जहांगीर रोड इत्यादि।

अतः माननीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार से मांग करता हूं कि मार्गों का नाम भारत को गुलाम बनाने वालों से हटाकर राष्ट्र भक्तों के नाम पर किया जाए जो कि भारतवासियों के जनभावना की अनुकूल है।